RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक:332
दि. 05.04.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मोदी बोले: केरलम में एलडीएफ जाएगी, एनडीए आएगी: पहले भी यहां आया, इस बार हवा का रुख कुछ और

● राज्य में घर से वोटिंग की सुविधा

नई दिल्ली/ तिरुवनंतपुरम/गुवाहाटी/कोलकाता/ चेन्नई,एजेंसी। केरलम के थिरुवल्ला पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि इस बार के चुनाव में केरलम में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) की सरकार जाएगी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की सरकार आएगी।

उन्होंने कहा कि मैं पहले भी केरलम आया हूं, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। केरल एक ऐतिहासिक बदलाव के लिए तैयार है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा।

चुनाव आयोग ने केरल के पलक्कड़ की तस्वीर शेयर की है। इसमें पलक्कड़ के कोंगड में 100 साल की महिला कुचम्मा ने घर से वोटिंग की।

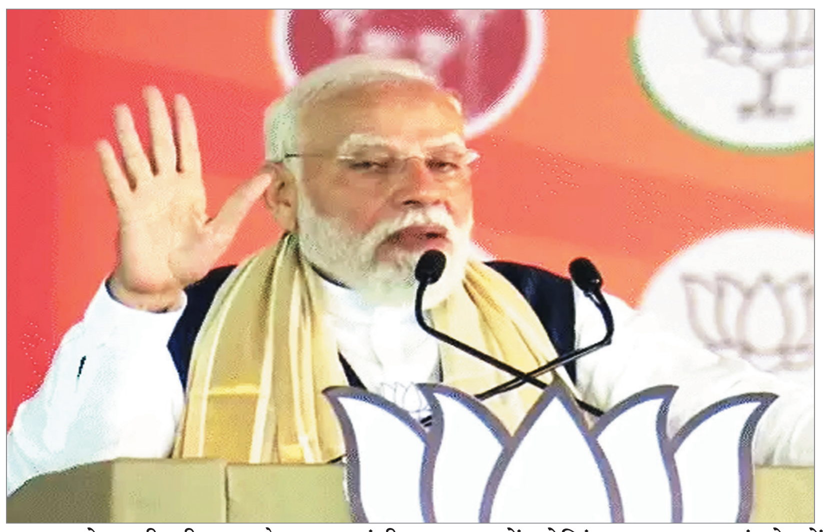

आयोग की टीम उनके घर पहुंची और होम वोटिंग सुविधा का लाभ दिया। राज्य में पोलिंग बूथ पर पहुंचने में असमर्थ लोगों को घर से वोटिंग की सुविधा है।

▶▶ **पीएम बोले- कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को गाली दे रही:** पीएम ने कहा कि कांग्रेस गल्फ कंट्रीज को गाली देने के का काम कर रही है, जिसे वे देश नाराज हो जाएं और वहां मौजूद भारतीयों को परेशानी है।

▶▶ **पीएम बोले- केरल में युवा रोजगार के लिए परेशान:** आज केरलम में युवाओं का पलायन सबसे बड़ी चिंता है। यहां रोजगार के लिए इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। यहां सर्विस सेक्टर बने, स्टार्टअप को जगह मिले, सही वेल्यू मिले। लेकिन यहां सबसे बड़ी दीवार करप्शन और कम्युनिलज्म है। जब ये दीवार टूटेगी तभी केरलम का विकास होगा। इसके लिए एलडीएल और यूडीएल को हराना होगा।

मोदी बोले- केरलम को बहुत फायदा, मेरा नुकसान: पीएम मोदी ने कहा- इस चुनाव में केरलम को कुछ फ़ायदा होने की संभावना है। लेकिन मेरे लिए पर्सनली, बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप सोच रहे होंगे कि जब मोदी को नुकसान हो रहा है तो केरलम को कैसे फायदा हो सकता है? मतल अनूप, जो यहां चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले पांच सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरे देश में घूमकर जानकारी और जानकारी इकट्ठा की है। एक तरह से, वह मेरे पक्के साथी रहे हैं और ऐसे काम के लिए मेरे दाहिने हाथ की तरह बन गए हैं।

ममता बनर्जी बोलीं- मालदा हिंसा में मुख्य आरोपी फरार, निर्दोषों को उठाया जा रहा

केरल में होम वोटिंग जारी, 100 साल की महिला ने मतदान किया

नई दिल्ली/ तिरुवनंतपुरम/ गुवाहाटी/ कोलकाता/ चेन्नई ,एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा के मोथाबाड़ी में हुई हिंसा और न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में केंद्र एजेंसियों पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि असली आरोपी फरार हैं, जबकि एनआईए स्थानीय लोगों को परेशान कर रही है। निर्दोष युवाओं को उठाया जा रहा है।

मालदा में ही रैली के दौरान ममता ने कहा- कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि राजनीतिक प्रदर्शन से बचें। प्रभावित लोग ट्रिब्यूनल में आवेदन देकर नाम जुड़वाएं। भाजपा हिंसा भड़काना चाहती है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। इधर, चुनाव आयोग ने केरल के पलक्कड़ की तस्वीर शेयर की है। इसमें पलक्कड़ के कोंगड में 100 साल की महिला कुंचम्मा ने घर वोटिंग की। आयोग की टीम उनके घर पहुंची और होम वोटिंग सुविधा का लाभ दिया।

राज्य में चलने में असमर्थ लोगों को घर से वोटिंग की सुविधा है।

केरल में सांसद शशि थरूर का काफिला रोका :ड्राइवर-गनमैन से हाथापाई

बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन से धक्का-मुक्की, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरा

नई दिल्ली/ तिरुवनंतपुरम/ गुवाहाटी/ कोलकाता/ चेन्नई, एजेंसी। केरल में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले को रोककर उनके गनमैन और ड्राइवर पर हमला किया गया। घटना शुक्रवार शाम करीब 7.30 बजे मल्लपुरम के वांडुर में हुई। पुलिस के मुताबिक थरूर सुरक्षित हैं।घटना के समय थरूर चुनावी सभा के लिए तिरुवल्ली जा रहे थे। 5 आरोपियों में से एक को हिरासत में लिया गया है। हमले का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

युद्ध के बीच शांति खोजने अल्मोड़ा पहुंचे इजराइली

टूरिस्ट बोला- घर पर लगातार बम-धमाकों की आवाजें आती हैं, यहां आकर सेफ फील करते हैं

अल्मोड़ा,एजेंसी। इजराइल में जारी युद्ध और लगातार बने तनावपूर्ण हालात के बीच वहां के लोग शांति की खोज में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहुंच रहे हैं। यहां पर स्थित कसार देवी क्षेत्र इजराइली टूरिस्टों के लिए ऐसा सुरक्षित और शांत ठिकाना बना हुआ है, जहां वे कुछ समय के लिए युद्ध के माहौल से दूर सुकून के पल बिता रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी इजराइली पर्यटक यहां पहुंचे हैं। हालांकि इस बार उनकी संख्या पहले के मुकाबले कम है। वीकेंड के दौरान जहां पहले 250 से 300 विदेशी पर्यटक पहुंचते थे, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर करीब 100 से 120 के बीच रह गया है। इसी बीच इजराइली समुदाय का प्रमुख धार्मिक पर्व 'पासओवर' भी इन दिनों चल रहा है, जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 9 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इस पर्व के बीच ये विदेशी मेहमान शांत वादियों के बीच अपना समय बिता रहे हैं। अल्मोड़ा शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित कसार देवी क्षेत्र लंबे समय से ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना का केंद्र रहा है। देवदार और चीड़ के जंगलों से घिरा यह इलाका शांत वातावरण और हिमालय के सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। दशकों से विदेशी पर्यटक यहां मानसिक शांति और ध्यान के लिए आते रहे हैं। साल 1850 के आसपास से ही इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो गई थी। पहले यहां मुख्य रूप से विदेशी ही पहुंचते थे, लेकिन कोविड के बाद देश के पर्यटकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। अपने मेडिटेटिव माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के कारण हर हफ्ते यहां पर करीब सौ से सवा सौ तक विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं, इनमें से ज्यादातर इजराइली हैं।

पासओवर के चलते पहुंचे 100 से ज्यादा इजराइली : पासओवर पर्व के चलते इस सप्ताह करीब 110 से ज्यादा इजराइली अल्मोड़ा पहुंचे हैं। इनमें से अधिकतर कसार देवी और उसके आसपास के क्षेत्रों में ठहरे हुए हैं, जहां वे अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ इस पर्व को मना रहे हैं।

हर साल इस दौरान यहां विदेशी पर्यटकों की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिलती है, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय हालातों का असर साफ दिखाई दे रहा है। संख्या बनी हुई है, लेकिन पहले जैसी भीड़ नहीं है, जिससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय पर भी असर पड़ा है।

दावा- राघव चड्ढा को केजरीवाल के घर मुर्गा बनाकर पीटा

हरियाणा आप पूर्व अध्यक्ष बोले- आंख पर चोट आई, इसका इलाज कराने इंग्लैंड गए सांसद

पंचकूला,एजेंसी। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। हरियाणा से के प्रदेश अध्यक्ष रहे नवीन जयहिंद ने नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयहिंद ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि राघव चड्ढा को दिल्ली में केजरीवाल के शीशमहल (सीएम हाउस) में बुलाकर मुर्गा बनाकर पीटा गया था। 4 नेताओं के सामने उनसे मारपीट हुई थी। जयहिंद ने यह भी कहा कि पिटाई में राघव की आंख पर चोट आई थी। इस चोट का इलाज कराने के लिए ही राघव इंग्लैंड गए थे। लोगों ने समझा कि राघव हनीमून मनाने के लिए इंग्लैंड गए हैं। राघव को सारे खुलासे खुलकर करने चाहिए। उधर, राघव चड्ढा ने भी उपनेता पद से हटाए जाने के बाद शुक्रवार को अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा था कि मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। आम आदमी को ये मेरा संदेश है।

23 साल बाद दुश्मन ने गिराया अमेरिकी फाइटर जेट:

ट्रम्प का ईरानी आसमान पर कब्जे का दावा गलत; अब तक अमेरिका के 7 विमान तबाह

वॉशिंगटन डीसी/ तेहरान,एजेंसी। ईरान जंग के एक महीने बाद ट्रम्प ने 2 अप्रैल को अमेरिकी जनता को संबोधित किया। 19 मिनट के भाषण में उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की हवाई सेना को तबाह कर दिया है और उनके पास जवाब देने की क्षमता नहीं बची है।ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका का ईरान के आसमान पर कब्जा हो चुका है। उनके विमान तेहरान के ऊपर उड़ रहे हैं और ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी ऐसे ही दावे किए। लेकिन हालात अब अलग कहानी बता रहे हैं। पिछले 24 घंटों में अमेरिका के दो सैन्य विमान और सर्च ऑपरेशन में लगे दो ब्लैकहॉक

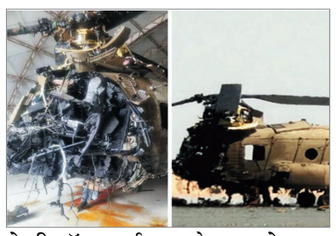

हेलीकॉप्टर ईरान के हमले का शिकार हुए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, 23 साल में पहली बार अमेरिकी लड़ाकू विमान दुश्मन की गोलीबारी में गिराए गए। इससे पहले 2003 में इराक युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था।ईरान जंग में अब तक 7 अमेरिकी विमान नष्ट हो चुके हैं 2 मार्च: कुवैत में 'फ्रेंडली फायर' में 3 F-15 गिरे, सभी 6 क्रू मेंबर सुरक्षित निकले।

नासिक में बड़ा हादसा, कुएं में कार गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत

नासिक,एजेंसी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक कार के कुएं में गिरने से एक परिवार के छह बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। हादसा शुक्रवार रात करीब 10 बजे डिंडोरी शहर के शिवाजी नगर इलाके में हुआ।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित परिवार एक बैंक्वेट हॉल में फंक्शन में शामिल होने के बाद घर जा रहे थे, तभी उनकी कार वेन्यू के पास एक कुएं में गिर गई। लोग मौके पर पहुंचे और आधी रात को दो क्रेन और तैराकों की मदद से कार और उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला।

पुलिस के अनुसार, मरने वालों की पहचान सुनील दत्तू दरगुडे (32), उनकी पत्नी रेशमा, एक अन्य महिला आशा अनिल दरगुडे (32) और परिवार के छह बच्चों (पांच लड़कियां और एक लड़का) के रूप में हुई है।

अधिकारी ने कहा कि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर को कुआं कैसे नहीं दिखा। उन्होंने आगे कहा, हम चश्मदीदों की तलाश कर रहे हैं और घटना के CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं।

देश में आय का 40% तक स्मार्टफोन खर्च पहुंचा, केवल 5% होना चाहिए

महंगाई ने 22 करोड़ यूजर्स का स्मार्टफोन अपग्रेड अटकाया

नई दिल्ली,एजेंसी। देश में 22 करोड़ लोग फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। वे स्मार्टफोन पर शिफ्ट होना चाहते हैं। पर बजट और महंगे हैंडसेट बड़ी बाधा हैं। एक भरोसेमंद स्मार्टफोन और एंट्री-लेवल फीचर फोन के बीच ?4-6 हजार का अंतर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेमोरी चिप की कीमतें बढ़ने से अंतर 6-8 हजार हो सकता है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक महंगे स्मार्टफोन डिजिटल इंडिया के लिए चुनौती हैं। बेसिक स्मार्टफोन की कीमत यूजर की मासिक आय का 30-40% तक है।

यह सामर्थ्य के तय मानक 5% से कई गुना है। सिंधिया ने सुझाव दिया है कि पीएलआई स्कीम को मेक इन इंडिया से आगे बढ़ाकर 'अफोर्डेबल इन इंडिया' की दिशा में ले जाना चाहिए।

हिस्सेदारी : 5-10 हजार सेगमेंट: बाजार हिस्सेदारी 24% है और इसमें 71% मॉडल अब 5जी तकनीक वाले हैं।

15 हजार से कम सेगमेंट: इसकी कुल मार्केट हिस्सेदारी 4% रह गई है और इसमें 100% मॉडल 4जी हैं।

फीचर फोन से 7 गुना महंगा स्मार्टफोन : देश का सबसे सस्ता 4जी स्मार्टफोन आईटेल जेनो 5799 रुपए का है। वहीं लावा शार्क 8999 रुपए में सबसे सस्ता 5जी स्मार्टफोन विकल्प है। इसके मुकाबले स्नेक्सलैन गुरु 301 जैसा 2जी फीचर फोन महज 649 और कार्बन के1 जैसा 4जी फीचर फोन मात्र 835 रुपए में उपलब्ध है।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर विपक्ष की सर्वदलीय बैठक की मांग, खरगे ने रिजिजू को लिखा पत्र

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023' के लागू करने के तरीकों और रोडमैप पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग दोहराई है। इस पत्र पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव समेत 10 से अधिक विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। खरगे ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने 16 मार्च, 2026 को भी किरेन रिजिजू को लिखा था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सरकार अब सितंबर 2023 में पारित इस संविधान संशोधन में एक और संशोधन की योजना बना रही है। विपक्षी दलों ने इस प्रस्तावित संशोधन पर चर्चा के लिए बैठक की मांग की है। खरगे ने कहा कि बैठक को अधिक उत्पादक बनाने के लिए सरकार को पहले एक नोट जारी करना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि वास्तव में क्या प्रस्तावित किया जा रहा है। बैठक विधानसभा चुनावों

का मौजूदा दौर पूरा होने के बाद 29 अप्रैल को आयोजित की जाए। इससे पहले 16 मार्च को रिजिजू ने खरगे को पत्र लिखकर कहा था कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने इसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता पर जोर दिया था और कांग्रेस नेतृत्व से विस्तृत बातचीत का आग्रह किया था। इसके जवाब में खरगे ने सर्वदलीय बैठक की मांग करते हुए कहा था कि यह कानून सितंबर 2023 में बिना किसी सहमति के पारित हुआ था और अब 30 महीने बाद सरकार इसके लागू करने के तरीकों पर चर्चा करना चाहती है।

पश्चिम एशिया तनाव का असर

भारत में बोतलबंद पानी महंगा होने की आशंका, आपूर्ति बाधित होने से उद्योग पर दबाव

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत में जहां एक ओर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की चेतावनी है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में अमेरिका- इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और आपूर्ति बाधित होने से देश का लगभग 6 अरब डॉलर का बोतलबंद पानी उद्योग दबाव में है, जिससे आने वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। भारत में अप्रैल और मई के महीनों में पानी और ठंडे पेय पदार्थों की मांग चरम पर होती है। ऐसे समय में साफ पेयजल की कमी, भूजल प्रदूषण और बुनियादी ढांचे की खामियों के कारण बड़ी आबादी बोतलबंद पानी पर निर्भर रहती है। डेटा फॉर इंडिया के अध्ययन के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लगभग 15% और ग्रामीण क्षेत्रों के 6% परिवार पीने के लिए पैकेज्ड पानी का उपयोग करते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है।

● **पूरे पैकेजिंग उद्योग पर असर की आशंका :** केमको प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के निदेशक वैभव सराओगी का कहना है कि पीईटी प्रीफॉर्म की कीमतों में वृद्धि का असर केवल बोतलबंद पानी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पैकेजिंग उद्योग को प्रभावित करेगा। उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियों के लिए लंबे समय तक लागत को खुद वहन करना संभव नहीं होगा। यदि कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं और आपूर्ति बाधित रहती है तो आने वाले हफ्तों में बोतलबंद पानी सहित अन्य पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि तय मानी जा रही है, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

● **महाराष्ट्र में 20% इकाइयों में उत्पादन बंद :** महाराष्ट्र बोतलबंद पानी निर्माता संघ के अध्यक्ष विजय सिंह दुब्बल के अनुसार पीईटी प्रीफॉर्म जिनसे प्लास्टिक बोतलें बनाई जाती हैं, उनकी कीमत 115 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर लगभग 180 रुपये हो गई है और बाजार में इनकी कमी भी देखी जा रही है। कच्चे माल की बढ़ती लागत और आपूर्ति संकट के कारण महाराष्ट्र में लगभग 20% बोतल निर्माण इकाइयों ने अस्थायी रूप से संचालन बंद कर दिया है।

बंगाल में अराजकता : संवैधानिक संस्थाओं की अग्निपरीक्षा

संपादकीय

पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत निर्वाचन नामावलियों के निस्तारण में लगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। इन सात बंधक अधिकारियों में तीन महिलाएं भी शामिल थीं जिन्हें नौ घंटे तक बिना खाना-पानी के रोके रखा गया। स्वाभाविक रूप से इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव व डीजीपी समेत कई उच्च अधिकारियों का कारण बताओ नोटिस भी दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। पिछले महीने तक साठ लाख में 47 लाख आपत्तियों का निस्तारण होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संतुष्टि व्यक्त की है। बहरहाल, इसके बावजूद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है तो उसका निस्तारण निर्धारित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है। बहरहाल, मालदा का यह घटनाक्रम कानून व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी अग्निपरीक्षा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल को राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत तथा चुनाव आयोग ने राज्य में जंगलराज होने की बात कही है। ध्यान रहे कि इससे पहले भी निर्वाचन अधिकारियों से मारपीट व घेराव की घटनाएं सामने आई हैं। जाहिर बात है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ लोगों में असंतोष है। मतदाता सूची से नाम कटने वाले लोगों की तल्ख प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। लेकिन यह तंत्र के प्रति बढ़ते अविश्वास का भी प्रतीक है, जिसके चलते ही घटनाक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पश्चिम बंगाल में इस महीने होने वाले चुनाव से पहले कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब राज्य में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल में इस माह की 23 व 29 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में मालदा का घटनाक्रम निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए चुनौती दर्शाने वाला है।

बहरहाल, मालदा के कालियाचक में भीड़ द्वारा अभिव्यक्त आक्रोश और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का घटनाक्रम यह बताता है कि लोगों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर व्यापक असंतोष है। यद्यपि कानून व्यवस्था को हाथ में लेना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही घटना का आकलन न कर पाना और समय रहते कार्रवाई न करना, तंत्र की विफलता को ही दर्शाता है। जिसे कानून व्यवस्था की नाकामी ही कहा जा सकता है। जब राज्य में एसआईआर काम में लगे लोगों को पहले से लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा था, तो इस कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

क्षितिज के पार : लहरों पर लिखती भारत की नई शौर्यगाथा

दिलीप कुमार पाठक

(5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस)

उफनती लहरें, गहरा नीला समंदर और क्षितिज पर डूबता सूरज–ये दृश्य अक्सर हमें सुकून देते हैं, लेकिन इसी असीम विस्तार के पीछे छिपी है एक राष्ट्र के स्वाभिमान और समृद्धि की वह कहानी, जिसे हम राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में याद करते हैं। यह दिन केवल एक तारीख भर नहीं है, बल्कि यह उस साहस का उत्सव है जिसने सदियों पहले विदेशी बेड़ियों को तोड़कर खुले समुद्र में अपनी पहचान दर्ज की थी। कल्पना कीजिए उस दौर की, जब समंदर पर केवल फिरंगियों का राज हुआ करता था। उनके जहाज चलते थे, उनके नियम चलते थे और हमारी अपनी विरासत कहीं किनारे पर खड़ी असहाय नजर आती थी। ऐसे में एक हिंदुस्तानी जहाज, एसएस लॉयल्टी, मुंबई के तट से लंदन के लिए निकलता है। वह सिर्फ लकड़ी और लोहे का ढांचा नहीं था, वह करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का वह पुल था जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाएं केवल जमीन तक सीमित नहीं हैं। वह यात्रा एक विद्रोह थी, एक घोषणा थी कि अब हम लहरों के साथ बहेंगे नहीं, बल्कि उन्हें अपनी दिशा में मोड़ेंगे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वह एक छोटी सी शुरुआत आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुकी है। भारत की करीब साढ़े सात हजार किलोमीटर लंबी तटरेखा केवल भूगोल का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। हमारे बंदरगाह आज केवल सामान उतारने और चढ़ाने की जगह नहीं रह गए, वे आधुनिक भारत के वे द्वार बन चुके हैं जहाँ से आत्मनिर्भर भारत का सपना दुनिया के बाजारों तक पहुँच रहा है। देश का लगभग 95% व्यापार आज भी इन्हीं लहरों के रास्ते होता है। ज़रा सोचिए, उन गुमनाम नाविकों के बारे में जो महीनों तक अपनों से दूर, अनजानी हवाओं और तूफानी लहरों के बीच डटे रहते हैं ताकि हमारे घरों के चिराग जलते रहें और कारखानों के पहिए घूमते रहें। उनका त्याग इस समुद्री प्रगति का असली आधार है।

अक्सर हम हिमालय की ऊंचाइयों की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन दक्षिण में फैले इस विशाल रत्नगर्भा नीले समंदर की गहराई को भूल जाते हैं। आज भारत जिस नीली अर्थव्यवस्था या ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहा है, वह भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है। गहरे समुद्र से निकलने वाले खनिज हों या तटों पर बसते मछुआरे भाइयों का जीवन, हर एक बिंदु इस विशाल तस्वीर का हिस्सा है। आधुनिक तकनीक ने अब हमें वह सामर्थ्य दे दिया है कि हम समंदर से न केवल संपदा निकाल रहे हैं, बल्कि उसकी रक्षा करना भी सीख रहे हैं। प्लास्टिक के प्रदूषण से लेकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों तक, आज का भारत एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति बनकर उभर रहा है। आज हम केवल व्यापारिक जहाज ही नहीं चला रहे, बल्कि समंदर की लहरों पर अपना स्वदेशी आईएनएस विक्रांत जैसा विमानवाहक पोत भी लहरा रहे हैं। यह उस तकनीकी कौशल का प्रमाण है जो बताता है कि हम रक्षा और सुरक्षा के मामले में भी अब किसी के मोहताज नहीं हैं। हिंद महासागर में भारत की बढ़ती धमक यह सुनिश्चित करती है कि यह क्षेत्र शांति और प्रगति का केंद्र बना रहे। सागर का जो विजन हमारे विज़नरी लोगों ने दिया है, वह केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सुरक्षा और विकास का मंत्र है। जैसे-जैसे दुनिया सिमट रही है और व्यापार के नए गलियारे खुल रहे हैं, समुद्र का महत्व और बढ़ता जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी को अब इन लहरों में छिपे करियर और एडवेंचर को पहचानना होगा। यह केवल जहाजों का संचालन नहीं है, यह वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था की वह धुरी है जहाँ भारत अब अगली कतार में खड़ा है। जब तक सूरज की किरणें इन लहरों पर चमकती रहेंगी, भारत की यह समुद्री यात्रा निरंतर चलती रहेगी। आज का दिन रुककर उन लहरों को सलाम करने का है, जिन्होंने हमें दुनिया से जोड़ा। उन पूर्वजों को नमन करने का है, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस नहीं खोया। और सबसे बढ़कर, उन युवाओं को प्रोत्साहित करने का है जो आने वाले समय में भारत की इस गौरवगाथा को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समुद्र हमें सिखाता है कि शांत रहकर भी विशाल कैसे बना जाता है और चुनौतियों के थपेड़ों को सहकर भी अपनी मंजिल कैसे पाई जाती है।

पश्चिम बंगाल बढ़ती अराजकता: लोकतंत्र के लिए चुनौती

पश्चिम बंगाल, जो कभी सांस्कृतिक चेतना, बौद्धिकता और राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक माना जाता था, आज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की जड़ें लगातार कमजोर होती प्रतीत हो रही हैं। जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राज्य में हिंसा, अराजकता अलोकतांत्रिकता और राजनीतिक असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घटते सम्मान और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति का भी द्योतक है। हाल ही में मालदा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अर्थात एसएआर को लेकर जिस प्रकार का असंतोष और तनाव देखने को मिला, वह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को दर्शाता है। मतदाता सूची में नाम जुड़ना या हटना एक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसके लिए स्पष्ट नियम और प्रावधान होते हैं।

ललित गर्ग

यदि इस प्रक्रिया को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा या प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जाएगा, तो निष्पक्ष चुनाव की पूरी प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाएगी। एसएआर प्रक्रिया में बाधक बनते हुए जिसे तरह से न्यायिक अधिकारियों को नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने की घटना सामने आयी है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के लिये एक गंभीर चेतावनी भी है। यह उस व्यापक घातक एवं विडम्बनापूर्ण प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र को भी राजनीतिक दबाव और भीड़तंत्र के आगे झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष रूप से यह तथ्य कि बंधक बनाए गए अधिकारियों में महिलाएं भी शामिल थीं, इस घटना को और अधिक गंभीर बना देता है। यह न केवल कानून के शासन पर प्रश्नचिह्न लगाता है, बल्कि समाज में बढ़ती असंवेदनशीलता को भी उजागर करता है।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास नया नहीं है। 1960 और 70 के दशक में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था, उसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद वामपंथी शासन के लंबे कालखंड में भी राजनीतिक विरोधियों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा की घटनाएं समय-समय पर सामने आती रहीं। सत्ता परिवर्तन के बाद तृणमूल कांग्रेस एवं ममता बनर्जी के शासन में यह प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई, बल्कि नए स्वरूप में सामने आई। यह स्पष्ट संकेत है कि समस्या केवल किसी एक दल या विचारधारा की नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक तंत्र में व्याप्त एक गहरे संकट की है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, चुनावों के निकट आते ही जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, वे लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का संकेत देती हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्य में लगे अधिकारियों को बंधक बनाना यह दर्शाता है कि कुछ तत्व चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार पर सीधा हमला है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता उल्लेखनीय है। समय-समय पर न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश दिए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाई है। किंतु यह भी एक चिंताजनक तथ्य है कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर अपेक्षित प्रभाव नहीं दिखाई देता। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्य प्रशासन एवं सत्तारूढ पार्टी इन निर्देशों को लागू करने में अक्षम है या इच्छुक नहीं है? यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी प्रभावी नहीं हो पा रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चुनाव के समय बढ़ती अराजकता के पीछे राजनीतिक बौखलाहट भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। जब किसी दल को अपनी लोकप्रियता में गिरावट का भय होता है, तो वह अक्सर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को दरकिनार कर असंवैधानिक उपायों का सहारा लेने लगता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसी ही प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं, जहां सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं पर विपक्ष को डराने, प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं। यदि इन आरोपों में सच्चाई है, तो यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

नागरिक समाज सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक केवल प्रशासनिक उपायों से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें कानून का शासन, संस्थाओं की स्वतंत्रता और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति इन सभी पहलुओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यदि चुनाव प्रक्रिया ही निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रह जाती, तो लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता का विश्वास होता है, और यदि मतदाता को यह लगने लगे कि मतदाता सूची, चुनाव प्रक्रिया या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में काम कर रहा है, तो लोकतंत्र की विश्वसनीयता स्वतः कमजोर होने लगती है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक नाकामी का प्रश्न भी गंभीरता से सामने आता है। किसी भी राज्य में यदि अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं, न्यायिक अधिकारी तक बंधक बना लिए जाते हैं और पुलिस या प्रशासन समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाता, तो यह प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है। प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और सरकारी कार्यों को निर्भय वातावरण में संपन्न कराना होता है। यदि प्रशासन यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा है, तो इससे जनता में भय और अविश्वास दोनों बढ़ते हैं। जनता का विश्वास ही किसी सरकार की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और जब यही विश्वास डगमगाने लगता है, तो शासन की वैधता पर भी प्रश्नचिह्न लगने लगते हैं।

राजनीतिक दलों की भूमिका भी इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों के संवाहक भी होते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को संयम, कानून के सम्मान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करें। लेकिन जब राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कटु संघर्ष में बदल जाती है और कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल चुनाव को युद्ध नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्सव के रूप में देखें। आज आवश्यकता इस बात की है कि पश्चिम बंगाल की घटनाओं को केवल एक राज्य की समस्या न मानकर लोकतंत्र के लिए चेतावनी के रूप में देखा जाए। यदि प्रशासनिक तंत्र कमजोर होगा, राजनीतिक दल मर्यादा नहीं रखेंगे, और जनता का विश्वास कम होता जाएगा, तो लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र की रक्षा केवल संविधान या न्यायालय नहीं कर सकते, इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक निष्पक्षता और जनता की जागरूकताकृतीनों का संतुलन आवश्यक है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियां हमें यही संदेश देती हैं कि लोकतंत्र को केवल चुनाव से नहीं, बल्कि व्यवस्था की निष्पक्षता, कानून के शासन और नागरिक विश्वास से मजबूत बनाया जा सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है कि राज्य सरकार, चुनाव आयोग और न्यायपालिका मिलकर ठोस कदम उठाएं। कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए, दोषियों के खिलाफ त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हो और प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा जाए। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें। निश्चित ही यह समझना होगा कि लोकतंत्र की रक्षा केवल संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति एक चेतावनी है कि यदि समय रहते सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह अराजकता और गहराई तक फैल सकती है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है कि हम सभी मिलकर कानून, नैतिकता और सहिष्णुता के मूल्यों को पुनः स्थापित करें। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां से वह या तो लोकतांत्रिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ सकता है या अराजकता के गहरे गर्त में गिर सकता है। यह निर्णय न केवल राजनीतिक नेतृत्व, बल्कि पूरे समाज को मिलकर लेना होगा।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

खुलकर हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना चाहिए, मन की प्रसन्नता खुद सृजित की हुई दवा के समान है

किशन सनमुखदास भावनानी

> दुनियां में जिसके पास प्रसन्नता, मन की शांती, संतोष भरा मन हो वो भाग्यशाली और खुश इंसान है। केवल आज की ही क्यूं वो इंसान हर दुनियां मे खुश है। महाभारत मे धर्मराज युधिष्ठिर से एक यक्षने प्रश्न पुछा के हे धर्मराज सबसे बडा सुख कौनसा है इस प्रश्न के उत्तर के स्वरूप युधिष्ठिरजी ने कहा समाधान ही सर्वोत्तम सुख है। मनुष्य के पास बहुत सारा पैसा हो अछी शादीशुदा जिंदगी हो अच्छे माता पिता हो लेकिन मन मे संतोष व प्रसन्नता न हो तो ऐसा व्यक्ती आज की या किसी भी दुनिया मे खुश नही हो सकता।

आज की दुनिया मे पैसा अतिआवश्यक है। लेकीन मन का संतोष प्रसन्नता उससे भी अधिक आवश्यक है,और एक बात जो की आवश्यक है वो है आपकी सेहत, सेहत अछी हो तो व्यक्ती का जीवन आनंदमय होता है.वैसे तो कुदरत द्वारा रचित इस अनमोल खूबसूरत सृष्टि में रचनाकर्ता ने मानवीय जीवन में अनेक गुण दोषों को शामिल कर संजोया है, इसका उपयोग करने सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमता का भी सृजन कर दिया है। बस!! जरूरत है अब माननीय जीव को उसे गुण-दोष सुख-दुख खुशियां-गम प्रसन्नता-दुख इत्यादि का चुनाव कर अपने जीवन को सफल और असफल बनाएं उसके ऊपर है!! क्योंकि प्रसन्नता और सुख दुख भी बौद्धिक क्षमता के आधार पर माननीय जीव को खुद चुनना होता है! इसलिए आज हम इस पावन बेला पर मन की प्रसन्नता पर उसके गुणों, प्रक्रिया सुजन करने के तरीकों पर इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे।

साथियों बात अगर हम प्रसन्नता की करें तो खुलकर हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना, मन की प्रसन्नता खुद सृजित की हुई दवा के समान है, क्योंकि इसमें सब दुख तो नष्ट होते हैं,जीव अपने कर्म में असफल नहीं होता। बुद्धि तुरंत स्थिर रहती है। सामाजिक प्रतिष्ठा और गुणों की सुगंध दूर तक जाती है एक अलग हस्मुख व्यक्तित्व की हमारी छाया हमारे अपने परिचितों सहयोगियों पर पड़ती है। प्रसन्नता हमारा ऐसा अनमोल खजाना है, जिसे जितना लूटाएंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, खिलखिलाते चेहरे और प्रसन्नता की आंखों की चमक मनीषियों को दुर्लभ पूंजी है, क्योंकि प्रसन्नता सुकून से जीने की कुंजी है। यह खजाना तब बढ़ता है जब हम दूसरों की खुशीयों में अपनी खुशी को समाहित करते हैं। हमें छोटी-छोटी चीजों में प्रसन्नता, सुख ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, विश्वसनीय मन के भाव की खुशी का भाव अभूतपूर्व सफलता और दूरगामी सकारात्मक परिणाम होता है। आध्यात्मिकता, उदारता, परोपकार, सहनशीलता, सहिष्णुता इत्यादि मन की प्रसन्नता के प्रमुख स्त्रोतों में से कुछ हैं, जिनको जीवन में अपनाने की जरूरत को रेखांकित किया जा सकता है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता इंडेक्स रिपोर्ट इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय स्तरपर प्रसन्नता के मूल्यों की करें तो प्रसन्नता को हाई वैश्विक टॉनिक माना जाता है। प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है अलग-अलग देशों के प्रसन्नता से रहने के क्रमांक बताए जाते हैं, परंतु बहुत हैरानी की बात है प्रसन्नता इंडेक्स में अनेक पूर्ण विकसित देशों के साथ ही भारत भी पिछड़ा हुआ है जो रेखांकित करने वाली बात है!! विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में 146 देशों की रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड लगातार 5 वर्षों से प्रथम और डेनमार्क द्वितीय और आयरलैंड तृतीय स्थान

पर है।जबकि इस रिपोर्ट में भारत 136 वी रैंक पर है याने लास्ट टॉप टेन इतनी ख़राब हालात जो आश्चर्य वाली बात है।

साथियों बात अगर हम मन की प्रसन्नता के गुण एवं लाभों की करें तो, प्रसन्नता तो व्यक्ति का मानसिक गुण है, जिसे व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के अभ्यास में लाना होता है। प्रसन्नता व्यक्ति के अंतर्मन में छिपे उदासी, तृष्णा और कुंठाजनित मनोविकारों को सदा के लिए समाप्त कर देती है। वस्तुतः प्रसन्नता चुंबकीय शक्ति संपन्न एक विशिष्ट गुण है। प्रसन्नता दैवी वरदान तो है ही, यह व्यक्ति के जीवन की साधना भी है। व्यक्ति प्रसन्न रहने के लिए एक खिलाड़ी की भांति अपनी जीवन-शैली और दृष्टिकोण को अपना लेता है। उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता-असफलता, जय-पराजय, और सुख-दुख उसके चिंतन का विषय नहीं होता। वह तो अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है।प्रसन्नता मानवों में पाई जाने वाली भावनाओं में सबसे सकारात्मक भावना है। इसके होने के विभिन्न कारण हो सकते हैंः अपनी इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होना। अपने दिन-रात के जीवन की गतिविधियों को अपनी इच्छाओं के अनुकूल पाना। किसी अचानक लाभ से लाभांवित होना। किसी जटिल समस्या का समाधान प्राप्त होना।

साथियों बात अगर हम प्रसन्नता के लक्ष्यों की प्राप्ति की करें तो, प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। यदि वह असफल भी हो जाता है तो निराश होने और अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोष देने की अपेक्षा अपनी चूक के लिए आत्मनिरीक्षण करना ही उचित समझता है।ज्ञानीजन और अनुभवी बताते हैं कि प्रसन्नता जैसे दैवीय-वरदान से कुतर्की और षड्यंत्रकारी लोग सदैव वंचित रह जाते हैं। प्रसन्न व्यक्ति स्वयं को प्रसन्न रखकर दूसरों को भी प्रसन्न रखने की अद्भुत सामर्थ्य रखता है। प्रसन्नता को प्रभु-प्रदत्त संपदा समझने वाले व्यक्ति ही सदैव सुखी रहते हुए यशस्वी, मनस्वी, महान और पराक्रमी बनकर समाज और राष्ट्र के लिए आदर्श स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। प्रसन्नता ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। प्रसन्नता हमारा अनमोल खजाना है। प्रसन्नता को ज़रूर लुटाइए फ़िर देखिए, उसका खजाना बढ़ता चला जाएगा ।भलाई करना कर्त्तव्य नहीं, आनन्द है । क्योंकि वह प्रसन्नता को पोषित करता है । सबको प्रसन्न करने की शक्ति सब मंव नहीं होती । प्रसन्नता आत्मा को शक्ति प्रदान करती है । प्रसन्नतापूर्वक उठाया गया बोझ हल्का महसूस होता है। प्रसन्नता शब्द का प्रयोग मानसिक या भावनात्मक अवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें संतोष से लेकर तीव्र आनंद तक की सकारात्मक या सुखद भावनाएं शामिल हैं। इसका उपयोग जीवन संतुष्टि, व्यक्तिपरक कल्याण, यूडिमोनिया, उत्कर्ष और कल्याण के संदर्भ में भी किया जाता है इसलिए हर व्यक्ति ने इस गुण को अपने में समाहित कर जीवन को सफल बनाने के मंत्र को अपनाना चाहिए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि खुलकर हंसना, मुस्कुराना,प्रसन्न रहना चाहिए,मन की प्रसन्नता खुदसृजित की हुई दवा के समान है।दुनियां में मन का संतोष प्रसन्नता खुशी और अच्छी सेहत ही सबसे बड़ी पूंजी है।आज की दुनियां मे वो सबसे अधिक खुश है जिसके पास प्रसन्नता, मन की शांती, संतोष भरा मन है। (-संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र)

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com•garvigujarat2007@yahoo.com•Website : www.garvigujarat.co.in

असम के चुनावों का लखनऊ की सफाई पर पड़ा सीधा असर, हजारों की संख्या में सफाईकर्मी वोटिंग के लिए रवाना

लखनऊ, एजेंसी। इन दिनों शहर में बहुत सारे घरों-मोहल्लों से कूड़ा नहीं उठ रहा है। वजह ये है कि कूड़े का उठान करने वाली रामकी कंपनी (लखनऊ स्वच्छता अभियान) और लायंस एनवायरो के करीब 200 कर्मचारी असम विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए परिवार के साथ घर लौट गए हैं।इससे उन इलाकों में भी कूड़ा उठान पर असर पड़ा है जहां पर असम मूल के करीब 200 लोग निजी तौर पर घर-घर से कूड़ा उठाने का काम करते हुए आजीविका चलाते हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए आठ अप्रैल को मतदान होना है। माना जा रहा है कि मतदान के बाद सभी कर्मचारियों को वापस लौटने में 12 अप्रैल तक का समय लग सकता है। तब तक 50 हजार घरों के लिए कूड़ा उठान की समस्या बनी रहेगी।

वैकल्पिक कर्मचारियों से भी राहत नहीं: शहर के 77 वार्डों में रामकी कंपनी कूड़ा एकत्र करने काम करती है। इस कंपनी के करीब 600 कर्मचारी घरों से कूड़ा कलेक्शन का काम करते हैं। इनमें से करीब 150 कर्मचारी चुनाव में वोट डालने के लिए असम अपने घर चले गए हैं। कंपनी ने वैकल्पिक कर्मचारी लगाए हैं मगर लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। वजह ये है कि वैकल्पिक कर्मचारियों को सभी घरों के बारे पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में बहुत से ऐसे घर, मोहल्ले और अपार्टमेंट हैं जहां कूड़ा कलेक्शन के लिए कर्मचारी के न पहुंचने की शिकायतें हैं।

पूरा परिवार ही गया है घर: शहर के 33 वार्डों में लायंस एनवायरो कंपनी कूड़ा कलेक्शन का काम करती है। इस कंपनी के करीब 50 कर्मचारी असम अपने घर गए हैं। खास ये है कि कर्मचारी अकेले नहीं गए बल्कि पूरे परिवार को साथ लेकर गए हैं। इन कर्मचारियों के परिवार में अन्य सदस्य जैसे पत्नी, भाई आदि भी निजी तौर पर अलग-अलग इलाकों में घरों से कूड़ा उठाने का काम करते हैं। लायंस एनवायरो का भी दावा है कि उसने वैकल्पिक कर्मचारियों की तैनाती की है लेकिन यहां भी व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य नहीं है।

सड़कों पर भी दिखने लगे हैं कूड़े के ढेर: दोनों कंपनियों के कर्मचारियों और निजी कूड़ा एकत्र करने वालों को मिलाकर देखें तो शहर में करीब 50 हजार घरों से कूड़ा कलेक्शन प्रभावित है। इससे प्रभावित मोहल्लों और कॉलोनियों में भी सड़कों पर कूड़ा नजर आने लगा है।

पांच दिन से नहीं उठा घरों से कूड़ा: चौक के दिलाराम बारादरी मोहल्ले में रहने वाली पूनम ने बताया कि पांच दिन से कूड़ा लेने वाले नहीं आ रहे हैं। घरों में कूड़ा बढ़ता जा रहा है। बदबू फैल रही है। घर के आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं जा कूड़ा फेंका जा सके। इससे बहुत दिक्कत हो रही है। इसी इलाके में रहने वाली ममता ने बताया कि कई दिनों से कूड़ा लेने वाली गाड़ी नहीं आई है। घर में कूड़ा सड़कर बदबू दे रहा है। कोई सूचना भी नहीं है कि कब तक गाड़ी नहीं आएगी।

कंपनी का दावा...अलग से लगाए हैं कर्मचारी: रामकी कंपनी के परियोजना प्रमुख अभय रंजन का कहना है कि कुछ कर्मचारी बाराबंकी व आसपास से बुलाए गए हैं। वह नए हैं इससे कुछ जगह समस्या आ रही होगी मगर जहां से शिकायत आती है उसे तुरंत दूर कराया जाता है। लायंस एनवायरो के मुखिया रणधीर सिंह ने कहा कि वैकल्पिक कर्मचारी लगाए गए हैं। कहीं से समस्या की कोई शिकायत नहीं है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार: यदि कहीं पर कूड़ा कलेक्शन की समस्या आ रही है तो उसे दूर कराया जाएगा। कंपनियों को वैकल्पिक इंतजाम करना होगा। इस बारे में कंपनियों से भी बात की जाएगी कि अपने स्तर से निगरानी रखते हुए व्यवस्था में सुधार करें।-गौरव कुमार, नगर आयुक्त

स्मार्ट मीटर की सुस्त तकनीक, बिल जमा करने के बाद भी घंटों नहीं शुरू हो रही आपूर्ति

लखनऊ , एजेंसी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर व्यवस्था में तकनीकी खामियों और सर्वर लोड के कारण उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के बाद भी बिजली आपूर्ति में देरी झेलनी पड़ रही है। जागरूकता की कमी और सिस्टम फेल होने से समस्या बढ़ी है, जिससे उपभोक्ता और कर्मचारी दोनों परेशान हैं।शिव प्रकाश और अजयवीर तो उदाहरण हैं। यह हाल पूरे प्रदेश का है। प्रदेश में 13 मार्च से शुरू नई व्यवस्था लागू हुई है। 78 लाख उपभोक्ताओं में 70.50 लाख के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है। यह आटोमैटिक मोड में हैं। बैलेंस निगेटिव होते ही आपूर्ति बंद हो जाती है। बिल जमा होने पर दो घंटे के अंदर आपूर्ति चालू होने का दावा है, जबकि हकीकत एकदम अलग है। बिजली जमा करने के बाद भी उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इससे उपभोक्ता परेशान हैं। वे बिजली कार्यालयों पर हंगामा कर रहे हैं। निगमों के अवर अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक परेशान हैं। उनका दर्द निगमों के आंतरिक ह्वाट्सअप ग्रुप में भी दिख रहा है। अभियंता उपभोक्ताओं की रसीदें ग्रुप में डालते हैं और हालात बताते हैं। वे आपूर्ति शुरू कराने की गुहार लगाते हैं। क्योंकि कनेक्शन जोड़ना उनके हाथ में नहीं है। यह आटोमैटिक है। मैनुअल कार्य प्रदेशभर में बने 10 मीटर डाटा मैनेजमेंट सेंटर से होता है। अभियंता ग्रूप के जरिए इस सेंटर से गुहार लगाते हैं।

तकनीकी समस्या से बढ़ी मुसीबत: ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि परेशानी की वजह तकनीक भी है। सर्वर पर लोड अधिक है। उपभोक्ताओं तक बैलेंस का मैसेज पहुंचता नहीं है अथवा वे देखते नही हैं। कनेक्शन कटते पर सचेत होते हैं। कनेक्शन जोड़ने का दबाव बढ़ता है तो टेक्निकल फॉल्ट होता है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा भी कुछ ऐसा ही तर्क देते हैं। वे बताते हैं कि मीटर डाटा मैनेजमेंट (एमडीएम) का सर्वर लोड नहीं ले रहा है। स्मार्ट प्रीपेट मीटर के हार्डवेयर में चाइनीज उपकरण लगाए गए हैं।इसी तरह की अन्य तकनीकी खामियां हैं। लोड बढ़ते ही सिस्टम हैंग कर जाता है। ऐसे में तमाम उपभोक्ताओं का रीकनेक्शन (दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया) नहीं हो पाती। यही वजह है कि उपभोक्ताओं और अभियंताओं को कनेक्शन जुड़वाने के लिए लगानी पड़ रही है। निदेशक (वाणिज्य) पावर कार्पोरेशन प्रशांत वर्मा ने बताया कि तकनीकी कारणों से दो चार केस में देरी हो सकती है। 1912 पर शिकायत करें।

गंगा मैया मुझे ले जाओ, बच्चे लौटा दो, 100 साल की दादी की अंतिम विदाई बनी पोतों का अंतिम सफर

मेरठ , एजेंसी। मेरठ के इंचौली थाना इलाके के जलालपुर गांव के एक ही परिवार के तीन किशोर और एक युवक गंगा नदी में डूब गए। चारों युवक चचेरे भाई हैं। एक अन्य युवक को डूबने से बचा लिया गया। देर रात तक चले सर्च ऑपरेशन में चारों का सुराग नहीं लग सका। घटना शुक्रवार को दोपहर में करीब 3−30 बजे हस्तिनापुर के मखदूमपुर गंगा घाट पर हुई।पुलिस ने बताया कि डूबने वाले तीन किशोर और युवक 100 वर्षीय दादी भगवती देवी के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। अंतिम संस्कार के बाद चारों एक अन्य परिजन प्रदीप के साथ गंगा नदी में स्नान करने लगे। नहाते समय सभी गहरे पानी में चले गए।

स्थानीय लोगों ने प्रदीप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया लेकिन चारों भाई लहरों में ओझल हो गए। डूबने वालों में जलालपुर गांव के किसान कमल सिंह सैनी के दो बेटे एलएलबी का छात्र अभिषेक (21) व दसवीं का छात्र हिमांशु (17) और उनके छोटे भाई सोनू के दो बेटे 12वीं का छात्र दीपांशु (17) व दसवीं का छात्र प्रियांशु (15) हैं। मवाना सीओ पंकज लवानिया पुलिस बल और पीएसी के गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंचे।

चारों की मां का रो-रोकर बुरा हालमखदूमपुर घाट पर चार भाइयों के गंगा में डूबने के हादसे के बाद से जलालपुर गांव का हर घर शोक में डूबा है, हर आंख से बस आंसू बह रहे हैं। सैनी परिवार के चार चचेरे भाइयों के एक साथ गंगा में डूबने की खबर ने दो सगे भाइयों के हंसते-खेलते संसार को उजाड़ कर रख दिया है। चारों भाइयों की माताओं का रो-रोकर बुरा हाल है।

मातम में डूबा गांव, मां बोली- गंगा मैया मुझे ले जाओ... बच्चे लौटा दो : भिषेक और हिमांशु की मां बिजेंद्री बेटों के कपड़ों को सीने से लगाकर बार-बार बेसुध हो रही हैं। सोनू की पत्नी मुनेश का विलाप सुनकर ग्रामीणों की आंखें भी नम हो गई। मुनेश बार-बार एक ही गुहार लगा रही थीं गंगा मैया मुझे ले जाओ, मेरे बच्चों को लौटा दो।

चैनल हैक कर विदेशी यूट्यूबरों को महंगे दाम में बेचता था जालसाज, वाराणसी का आरोपी गिरफ्तार

वाराणसी, एजेंसी। यूट्यूब चैनल हैक करने वाले आरोपी सचिन राजभर को साइबर क्राइम सेल और फूलपुर पुलिस ने शुक्रवार रात पिंडरा से गिरफ्तार किया। मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनलों को टारगेट और हैक करने के बाद विदेशी यूट्यूबरों को महंगे दामों में बेचता था। गिरफ्तार आरोपी फूलपुर थाना क्षेत्र के पिंडरा रूप चंदपुर पारागडीह का निवासी है।एसीपी साइबर अपराध विदुष सक्सेना ने बताया कि सूचना पर टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में चिन ने बताया कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से यूट्यूब चैनल खरीदने का झांसा देकर पीड़ितों से उनके चैनल, जीमेल के लॉगिन क्रेडेंशियल्स लेता था। फिर दुरुपयोग कर चैनल हैक कर लेता था। साइबर सेल प्रतिबिंब टीम के प्रभारी हिमांशु त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अन्य आरोपों में बिहार और पंजाब में तीन प्राथमिकी दर्ज हैं।

साइबर सेल प्रभारी मनोज तिवारी ने बताया कि आरोपी का अन्य आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। फूलपुर पुलिस ने आरोपी का चालान किया है।

किसी को भी न बताएं अपना लॉगिन, पासवर्ड: एसीपी विदुष सक्सेना ने अपील की कि किसी भी ऑनलाइन नौकरी, निवेश, लॉटरी और प्रलोभन संबंधी प्रस्तावों पर विश्वास करने से पहले उसकी सत्यता जांच लें।

शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं, स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में बोले सीएम योगी

वाराणसी, एजेंसी। शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है, मनुष्य को मनुष्य बनाने का सशक्त माध्यम है। इस माध्यम को सफल बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर है, वे यदि परिश्रम करें अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो सफलता निश्चित मिलेगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षकों ने मेहनत किया और ऑपरेशन कायाकल्प को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हर घर से सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। ये बातें शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में आयोजित स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को काशी पहुंचे। शनिवार की सुबह शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय पहुंचे। यहां से पूरे प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने जिले के पांच निपुण विद्यालय, पांच निपुण बच्चे व पांच नव प्रवेशी बच्चों को सम्मानित किया। परिसर में शिक्षा से जुड़े 12 स्टॉल लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री इन स्टॉलों का अवलोकन भी किए। शिवपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय में अतिथियों का स्वागत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का भाषण व सम्मान कार्यक्रम से किया गया। सुबह 11:30 बजे तक कार्यक्रम का समापन होगा।

बेसिक शिक्षा मंत्री समेत कई अधिकारियों ने लिया हिस्सा: कंपोजिट विद्यालय, शिवपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। इनके साथ बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, डीजी मोनिका रानी, संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

यूपी में ओवरलोडिंग कर रहे 1600 वाहनों में 900 के टोल फर्जी नंबरों पर कटे, सूची देख चौकें अफसर

लखनऊ, एजेंसी। लखनऊ के टोल प्लाजाओं पर ओवरलोड वाहनों के फर्जी नंबरों से टोल काटने का बड़ा घोटाला सामने आया है। कई नंबर अस्तित्वहीन पाए गए। जांच में टोलकर्मियों की मिलीभगत और मैनुअल भुगतान के जरिए फर्जीवाड़ा उजागर हुआ।

इटौंजा टोल प्लाजा पर एक महीने के अंदर 1600 ओवरलोडेड वाहन गुजरे। इसमें 900 के टोल फर्जी नंबरों से काटे गए। चौकिए मत। ऐसे-ऐसे फर्जी नंबरों से टोल काटे गए हैं, जिनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। अफसरों को उन फर्जी नंबरों को ट्रैक करने में पसीने छूट गए। लेकिन उनका कहीं ओर-छोर नहीं मिला। न चेचिस, न ही नंबरों से वाहनों का विवरण मिला।

यह किसी एक टोल प्लाजा का मामला नहीं है। लखनऊ के सभी टोल प्लाजाओं पर ऐसी स्थिति है। फर्जी नंबरों पर ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों के टोल काटे जा रहे हैं। दरअसल, ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से निर्देशित किया गया।इसमें परिवहन सहित एचएचएआई, ट्रैफिक व अन्य विभागों को सख्ती बरतने को कहा गया। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई की ओर से टोल से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों का ब्योरा परिवहन विभाग को सौंपा गया।जब अधिकारियों ने सूची की पड़ताल की तो इसमें यह फर्जीवाड़ा सामने आया। इटौंजा टोल प्लाजा से जनवरी माह में 1600 ओवरलोड वाहन गुजरे। इनकी पड़ताल की जिम्मेदारी परिवहन विभाग के चार अफसरों को दी गई। जब अफसरों ने सूची जांची तो उनके होश उड़ गए।ऐसे-ऐसे नंबरों से ओवरलोड वाहनों के टोल काटे गए थे, जिनका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि 1600 वाहनों में करीब 900 के नंबर फर्जी पाए गए हैं। वहीं फरवरी माह में एनएचएआई की ओर से दी गई सूची के वाहनों में अभी तक 200 वाहन फर्जी पाए गए हैं।

फर्जी नंबर से कटा टोल, एफआईआर दर्ज: एआरटीओ(प्रवर्तन) आलोक कुमार यादव की टीम कानपुर रोड पर दरोगाखेड़ा में ओवरलोड वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच कानपुर से लखनऊ आ रहे ओवरलोडेड ट्रक यूपी 32 जेडएन 8925 की जांच की। उन्होंने बताया कि चालक लहरपुर(सीतापुर) निवासी मनीष से जब टोल की पर्ची मांगी गई तो उसने रसीद संख्या 1553972 थमाई।यह तीन अप्रैल की सुबह साढ़े चार बजे की पर्ची थी। वाहन संख्या जांचने पर एआरटीओ का माथा ठनक गया। उन्होंने देखा कि पर्ची पर वाहन संख्या(एमए 34 एस 9455) दर्ज था। इस नंबर से जब वाहन का विवरण जांचा गया तो ऑनलाइन कोई डिटेल ही नहीं उपलब्ध थी।

मेरठ शराब कांड पर सवाल, अलीगढ़ जैसी घटना के बाद भी नहीं चेता तंत्र, निगरानी और कार्रवाई पर घिरा प्रशासन

मेरठ, एजेंसी। मेरठ के दौराला क्षेत्र में मिलावटी शराब से तीन लोगों की मौत के आरोप ने एक बार फिर पुलिस और आबकारी विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब 2021 में अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में सख्ती के निर्देश दिए गए थे। अलीगढ़ कांड के बाद प्रदेश सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने और मिलावटी शराब के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। शुरुआती दिनों में पुलिस और आबकारी विभाग ने अभियान भी चलाया, लेकिन समय बीतने के साथ कार्रवाई की रफ्तार धीमी पड़ती चली गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दौराला और आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री और गुणवत्ता की निगरानी को लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई। शराब के ठेकों पर स्टॉक की जांच और गुणवत्ता की पड़ताल नियमित रूप से नहीं हो रही थी। हाल ही में मोदीपुरम स्थित मिलांज मॉल के शराब ठेके पर एक्सपायर बीयर मिलने का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद शिकायत पर छापेमारी की गई थी। इसी तरह लावड़ क्षेत्र में भी पहले एक शराब ठेके के सेल्समैन को संदिग्ध ढक्कनों के साथ पकड़ा गया था। उस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वही व्यक्ति फिर से ठेके पर काम कर रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग की कथित निष्क्रियता के कारण अवैध शराब का कारोबार क्षेत्र में फल-फूल रहा है।ग्रामीणों का कहना है कि लावड़ रोड के आझौता, समौली, खेड़ी और मवी जैसे गांवों में पहले भी कच्ची शराब को लेकर कई बार छापेमारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद यह धंधा गुपचुप तरीके से जारी है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद पुलिस की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही।दौराला की ताजा घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कब तक लापरवाही और अवैध शराब का कारोबार लोगों की जान लेता रहेगा।

एआई से जीएसटी चोरी पर वार, यूपी में फर्जी कारोबार और फर्मों की धर-पकड़ कर रहा 'बाइफा'

लखनऊ, एजेंसी। जीएसटी विभाग फर्जी फर्मों और टैक्स चोरी पकड़ने के लिए एआई और डेटा एनालिटिक्स आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। यह संदिग्ध लेनदेन और नकली बिलिंग को चिन्हित करता है। सख्ती के बावजूद जालसाज ई-वे बिल के जरिए धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है।उत्तर प्रदेश में फर्जी फर्में बनाकर टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए राज्य का जीएसटी विभाग अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का सहारा ले रहा है। इसमें मुख्य रूप से बाईफा (बिजनेस इंटेलीजेंस एंड फ्राड एनालिटिक्स) सॉफ्टवेयर की भूमिका सबसे अहम है।बाइफा विभाग का सबसे शक्तिशाली डिजिटल हथियार है जो भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों को रेड फ्लैग यानी चिह्नित कर देता है। यह टूल ट्रैक करता है कि क्या बिल केवल कागजों पर एक ही ग्रुप की कंपनियों के बीच घूम रहे हैं।राज्य कर विभाग में जांच से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाइफा विभाग का सबसे शक्तिशाली डिजिटल हथियार है। यह सॉफ्टवेयर भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों को रेड फ्लैग यानी चिह्नित कर देता है। यह टूल ट्रैक करता है कि क्या बिल केवल कागजों पर एक ही ग्रुप की कंपनियों के बीच घूम रहे हैं।

यह सिस्टम तुरंत अधिकारियों को अलर्ट भेज देता: यदि एक ही मोबाइल नंबर या पैन से कई फर्में रजिस्टर्ड हैं, तो यह सिस्टम तुरंत अधिकारियों को अलर्ट भेज देता है। यूपी का जीएसटी सिस्टम अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के टोल प्लाजा से रीयल-टाइम डेटा के साथ एकीकृत है। अगर किसी व्यापारी ने ई-वे बिल तो बनाया है, लेकिन वह ट्रक किसी टोल प्लाजा से नहीं गुजरा, तो सिस्टम समझ जाता है कि केवल कागजी सप्लाई हुई है।

उन्होंने बताया कि विभाग एआई का उपयोग करके करदाताओं के व्यवहार का विश्लेषण कर रहा है। यदि किसी नई फर्म का टर्नओवर बिना किसी ठोस आधार के अचानक करोड़ों में पहुंच जाता है, तो एआई टूल्स इसे संदिग्ध मानकर जांच के लिए भेज देते हैं।

गुजरात में टाइल्स फैक्ट्रियां बंद, 25 दिन से शहर नहीं आया माल

15 करोड़ का डेली बिजनेस प्रभावित

कानपुर , एजेंसी। गुजरात स्थित मोरबी की टाइल्स फैक्ट्रियां बंद होने से शहर का मारबल और टाइल उद्योग संकट का सामना कर रहा है। 25 दिन से मोरबी से टाइल्स की एक भी गाड़ी कानपुर नहीं आई है। इससे टाइल्स के दाम बढ़ गए हैं। भाव बढ़ने से ग्राहक भी बाजार में नहीं हैं। इसके चलते कारोबार से जुड़े दैनिक कर्मियों के सामने रोजी-रोटी का संकट हो गया है।शहर के किदवईनगर में टाइल्स और मारबल का बड़ा कारोबार होता है। यहां पर करीब 100 से ज्यादा दुकानें और शोरूम हैं। इसके अलावा शहर के अलग-अलग हिस्सों में भी 150 से ज्यादा दुकानें हैं। 10-15 करोड़ का प्रतिदिन का कारोबार होता रहा है। शहर के अलावा आसपास के जिलों को भी टाइल्स आदि की आपूर्ति की जाती है। अब आपूर्ति प्रभावित होने से संकट खड़ा हो गया है।

बड़ा बदलाव, पहले साल से इलेक्टिव कोर्स; एआई-डेटा साइंस की भी पढ़ाई अनिवार्य

लखनऊ, एजेंसी। एकेटीयू नए सत्र से एनईपी लागू कर पहले वर्ष से इलेक्टिव कोर्स शुरू करेगा। छात्र अन्य विषयों का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस को प्रैक्टिकल रूप में शामिल किया गया है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक कौशल, प्रोजेक्ट अनुभव और उद्योग से जुड़ने के अवसर मिलेंगे।डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) नए सत्र से एनईपी को पूरी तरह से लागू करने में जुट गया है। इसके तहत पहले साल से ही छात्रों को इलेक्टिव कोर्स लेने (पढ़ने) का विकल्प मिलेगा। वो दूसरे विषय से संबंधित जानकारी भी ले सकेंगे। वहीं अलग-अलग ब्रांच का सिलेबस भी अपडेट किया गया है। इसमें आज की जरूरत के अनुरूप एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस आदि को प्रैक्टिकल रूप में शामिल किया गया है।विश्वविद्यालय न केवल सैद्धांतिक ज्ञान देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि नए इलेक्टिव कोर्स के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक कौशल से भी युक्त करने की तैयारी कर रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। एकेटीयू के डीन यूजी प्रो. अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि हम चार क्रेडिट के कोर्स में 60 घंटे पढ़ाई कराएंगे। इसमें छात्र तीन थ्योरी और एक इलेक्टिव कोर्स ले सकेंगे।इसी तरह 30 घंटे का प्रैक्टिकल एक क्रेडिट का होगा। इतना ही नहीं हमने कोर्स को इस बार ऐसे डिजाइन किया है कि इलेक्ट्रिकल में अलग, मैकेनिकल में अलग गणित पढ़ाई जाएगी। जिसको जैसी जरूरत होगी, वैसा प्लान बनाया गया है। इमर्जिंग तकनीकी एआई, डेटा साइंस आदि को अनिवार्य किया गया है।

मानव मूल्यों व सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई भी: प्रदेश के इंजीनियरिंग संस्थानों के छात्र अब सिर्फ गणित व विज्ञान की तकनीकी जानकारी ही नहीं लेंगे। बल्कि एआईसीटीई के बदले हुए नियमों के तहत वे मानव मूल्यों, सामाजिक विज्ञान आदि की पढ़ाई भी करेंगे। इसके तहत एक्स्ट्रा कॅरिकुलर एक्टिविटी में 100 प्वाइंट तय किए गए हैं। छात्रों को एक साल में 25 प्वाइंट अर्जित करने होंगे। विश्वविद्यालय की ओर से नए सत्र के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है।

व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए करेंगे काम: एकेटीयू इन इलेक्टिव कोर्स के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव देगा। छात्रों को विभिन्न इलेक्टिव कोर्स में प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षा का अनुभव देगा। उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए अपने प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हुए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे।द्यविवि विभिन्न उद्योगों और प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा।

मार्बल के फर्जी बिलों से टैक्स चोरी, 8.62 लाख का जुर्माना; राज्य कर विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

आगरा , एजेंसी। राज्य कर विभाग ने चेकिंग के दौरान फर्जी बिल और ई-वे बिल के जरिए मार्बल की टैक्स चोरी का बड़ा मामला पकड़ा। एक ही पैन पर कई फर्म चलाकर संगठित तरीके से व्यापार किया जा रहा था, जिस पर 8.62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सहायक आयुक्त राज्य कर केदार नाथ ने तहरीर दी। उनके अनुसार 18 मार्च को सचल दल पंचम इकाई ने कोरई टोल प्लाजा के पास राजस्थान नंबर की लोडर को रोककर जांच की। वाहन चालक जफरुद्दीन अगावान ने बताया कि वह किशनगढ़ (राजस्थान) से ग्रेनाइट-मार्बल स्लैब लेकर आगरा आ रहा है। जांच के दौरान प्रस्तुत टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल में 8002 वर्गफीट माल दर्शाया गया, जबकि भौतिक सत्यापन में 11,244 वर्गफीट माल पाया गया। जांच में सामने आया कि विक्रेता फर्म एसआरके इंटरप्राइजेज (किशनगढ़) ने 23 फरवरी को जीएसटी पंजीकरण कराया लेकिन अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किए। इसके बावजूद लगातार ई-वे बिल जारी कर व्यापार किया जा रहा था। साथ ही एक ही पैन नंबर पर राजस्थान में आरके इंटरप्राइजेज और आगरा में एके इंटरप्राइजेज के नाम से फर्म संचालित होना पाया गया। फर्म का संचालक लवकुश बताया गया है। इसी मोबाइल नंबर और ईमेल से एक तीसरी फर्म जेके इंटरप्राइजेज भी संचालित पाई गई। यह भी सामने आया कि यह वाहन पहले 8 मार्च को महाराष्ट्र में टैक्स चोरी में पकड़ा जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार यह पूरा मामला सुनियोजित तरीके से फर्जी दस्तावेजों के जरिए टैक्स चोरी का है। एसीपी लोहामंडी गौरव कुमार ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

बरेली बवाल के तीन आरोपियों की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दिया गिरफ्तारी का आदेश

बरेली, एजेंसी। बरेली बवाल के तीन आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोपियों ने प्राथमिकी को गलत बताते हुए निरस्त करने की अपील की थी। बरेली शहर में 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के तीन आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। बता दें कि तीन आरोपियों ने प्राथमिकी को गलत बताते हुए उसे रद्द कराने के लिए याचिका दाखिल की थी।

इन आरोपियों ने दाखिल की थी याचिका : मौलाना तौकीर रजा के उकसावे पर शहर में बवाल, पुलिस पर हमला, दंगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में आरोपी साजिद सकलैनी, अजमल रफी और नईम कुरैशी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। आरोपियों ने वकील के जरिये कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि पुलिस ने गलत प्राथमिकी दर्ज की है। उनकी नामजदगी भी गलत है। ऐसे में कोर्ट से प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश पारित करने की याचिका की थी। साजिद सकलैनी को गिरफ्तारी पर स्टे मिला हुआ था। आरोपियों ने दावा किया था कि उनकी नामजदगी गलत है।

याचिका खारिज, गिरफ्तारी का आदेश : हाईकोर्ट ने आरोपियों की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए गिरफ्तारी का आदेश दिया है। आरोपियों में साजिद पर 15 हजार रुपये इनाम भी घोषित है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है।

बड़ा बाग हनुमान मंदिर और लीलौर झील समेत छह पर्यटन स्थलों का होगा सुंदरीकरण, बजट जारी

बरेली , एजेंसी। बरेली जिले में प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों के सुंदरीकरण के लिए प्रदेश सरकार ने बजट जारी किया है। इससे शहर स्थित बड़ा बाग हनुमान मंदिर समेत जिले के अन्य पर्यटन स्थलों पर विकास कार्य कराए जाएंगे। बरेली जिले के प्रमुख धार्मिक व पर्यटन स्थलों के लिए शासन ने बजट जारी किया है। 10.35 करोड़ रुपये से बड़ा बाग हनुमान मंदिर, लीलौर झील समेत कुल छह पर्यटन स्थल संवारे जाएंगे। इससे यहां आने वाले पर्यटकों को सहूलियत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हार्टमन स्थित बड़ा बाग हनुमान मंदिर के विकास के लिए 3.55 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। विकास भवन के सामने आनंद आश्रम के लिए 90 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे यहां आने वाले यात्रियों के लिए हॉल बनाया जाएगा। आंवला क्षेत्र में लीलौर झील पर 52 हेक्टेयर में काम कराया जा रहा है। इसके लिए पांच करोड़ रुपये की डिमांड शासन को भेजी गई थी। तीन करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। यात्री यात्री हॉल, फूड कोर्ट, टॉयलेट ब्लॉक, कैफेटेरिया बनाया जाएगा। पर्यटकों के लिए बोटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

इन स्थलों पर भी होंगे विकास कार्य : अहिच्छत्र किला, गुलड़िया गौरीशंकर मंदिर में भी ओपेन हॉल का निर्माण कराया जाएगा। आंवला क्षेत्र में स्थित जैन मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 2.50 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे वहां बड़ा यात्री हॉल, टायलेट, फूलों की दुकानें बनाई जा रही हैं। उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थित द्रौपदी स्वयंवर स्थल के लिए 90 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। यहां पेंटिंग म्यूरल बनाए जाएंगे। यह दीवार, छत या किसी अन्य बड़े स्थायी ढांचे पर सीधे बनाई गई कलाकृति होगी । क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि जिले के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शासन से 10.35 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इससे स्थलों का विकास होगा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। व्यापार बढ़ने के साथ लोगों को रोजगार भी मिलेंगे।

जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति, आंदोलन की दी चेतावनी

गोरखपुर , एजेंसी। जिला कांग्रेस कमेटी की मासिक समीक्षा बैठक शुक्रवार को जिलाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, जनसंपर्क अभियानों और क्षेत्र की प्रमुख जनसमस्याओं को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं पर चिंता जताई। खासतौर पर गैस सिलिंडर की कमी और कालाबाजारी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। नेताओं का आरोप था कि कृत्रिम किल्लत पैदा कर उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूली जा रही है, जिससे आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग परेशान है। जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने कहा कि प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। गैस सिलेंडर की कमी और उसकी कालाबाजारी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। चार अप्रैल को लखनऊ में बाबू जगजीवन राम जयंती कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग का निर्णय लिया गया। अंत में कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और जनहित के मुद्दों पर निरंतर संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

गुरुग्राम में घोटाला, 1500 अधूरी इमारतों को पूरा बताकर दिए ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट; आर्किटेक्ट होंगे ब्लैकलिस्ट

नया गुरुग्राम, एजेंसी। शहर की लाइसेंस कॉलोनियों में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जारी करने के नाम पर चल रहे बड़े खेल का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। बीते छह महीनों में जारी हुए ओसी अब सीएम फ्लाइंग की रडार पर हैं। शुरुआती जांच ने ही चौंकाने वाले तथ्य सामने ला दिए हैं। कई इमारतों में जहां निर्माण कार्य अभी अधूरा था, उन्हें पूर्ण बताकर ओसी जारी कर दिए गए। बृहस्पतिवार से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी प्लानिंग कार्यालय और सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने सेल्फ सर्टिफिकेशन नियमावली के तहत आर्किटेक्ट्स द्वारा जारी ओसी की जमीनी जांच शुरू कर दी है। दो दिनों के भीतर टीम ने अंसल एसेंसिया, अनंतराज, साउथ सिटी-1, साउथ सिटी-2 और सेक्टर-61 की अलग-अलग लाइसेंस कॉलोनियों में करीब 20 स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारतों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान जो सामने आया उसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। कई

इमारतों में जहां निर्माण कार्य अभी अधूरा था, वहीं उन्हें पूर्ण बताकर ओसी जारी कर दिए गए। सबसे गंभीर बात यह रही कि 20 में से कम से कम पांच इमारतें ऐसी मिलीं, जिनमें सिविल वर्क की शुरुआती अवस्था में ही ओसी जारी कर दिया गया था।

कुछ जगहों पर तो ईंटों के कच्चे ढांचे पर ही कागजी तौर पर तैयार इमारत घोषित कर दी गई। बता दें कि आर्किटेक्ट्स द्वारा जारी किए जा रहे ओसी पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे और टाउन प्लानिंग विभाग के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं। इसी के चलते सीएम फ्लाइंग ने डीटीपी प्लानिंग को पत्र लिखकर एक जुलाई 2025 से 15 मार्च 2026 तक जारी सभी ओसी की सूची मांगी थी। विभाग ने करीब 1500 ओसी की सूची तैयार कर जांच एजेंसी को सौंप दी है। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। अभी केवल जनवरी के बाद जारी किए ओसी की जांच पड़ताल की गई है। कई मामलों में बिना निर्माण पूर्ण हुए ही ओसी जारी किए गए हैं। सभी मामलों की विस्तृत जांच की जा रही है और इसकी पूरी रिपोर्ट चंडीगढ़ स्थित उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके बाद इसमें दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नियमावली में केवल 10 प्रतिशत ओसी जांच करने का प्राधान

टाउन प्लानिंग की नियमावली के हिसाब से डीटीपी प्लानिंग आर्किटेक्ट द्वारा विभाग में जमा करने वाली ओसी की फाइल्स में केवल 10 प्रतिशत फ़ाइलों की ही जांच कर सकता है। यह 10 प्रतिशत फ़ाइल भी विभाग का सॉफ्टवेयर रैंडम सेलेक्ट करता है। ऐसे में टाउन प्लानिंग के डीटीपी प्लानिंग कार्यालय की तरफ से सीएम फ्लाइंग टीम का पूरा सहयोग किया जा रहा है ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। सीएम फ्लाइंग ने विभाग को पत्र लिखकर 1 जुलाई 2025 से लेकर 15 मार्च 2026 तक आर्किटेक्ट द्वारा जारी किए गए आक्यूपशन सर्टिफिकेट की सूची मांगी थी जो कि विभाग ने मुहैया करा दी है। इसके अलावा जांच पड़ताल के लिए विभाग द्वारा एक एटीपी और जूनियर इंजीनियर की सहयोग के लिए सीएम फ्लाइंग टीम के साथ ड्यूटी लगाई है। जिस भी आर्किटेक्ट ने गलत ओसी जारी किए हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी।

गहरी सांस लेना तनाव कम करने का सबसे आसान तरीका

नई दिल्ली , एजेंसी। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव हृदय रोगों के खतरे को काफी बढ़ा सकता है, इसलिए समय रहते इसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है।

तनाव की स्थिति में शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं, जो ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे, तो हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ऐसे में कुछ सरल आदतों को अपनाकर न केवल तनाव को कम किया जा सकता है, बल्कि दिल को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। गहरी सांस लेना तनाव कम करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है। योग और आयुर्वेद में इसे प्राणायाम का हिस्सा बताया गया है, जो शरीर और मन को संतुलित करने में मदद करता है। जब व्यक्ति धीरे-धीरे और गहरी सांस लेता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है। इससे दिल की धड़कन सामान्य रहती है और मन शांत होता है।

इसके अलावा, नियमित रूप से वॉक करना या योगासन करना भी तनाव कम करने में बेहद लाभकारी है। एक्सरसाइज के दौरान शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं, जो मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं। साथ ही, यह ब्लड सर्कुलेशन को सुधारकर हृदय को मजबूत बनाने में मदद करता है। संतुलित और पौष्टिक आहार भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार सात्विक भोजन मन को शांत और स्थिर रखने में सहायक होता है। ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करता है और तनाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही डाइट सूजन को कम करती है और दिल की सेहत को बेहतर बनाती है।

अच्छी और पर्याप्त नींद भी तनाव प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने से शरीर को पूरा आराम मिलता है, हार्मोन संतुलित रहते हैं और हृदय पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। इसके साथ ही, नियमित मेडिटेशन करना मानसिक शांति के लिए बेहद प्रभावी माना जाता है। यह तनाव हार्मोन को कम करता है और मन को स्थिर बनाता है, जिससे हृदय की कार्यप्रणाली भी बेहतर होती है। मालूम हो कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव लगभग हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका है। काम का बढ़ता दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और बदलती जीवनशैली का असर धीरे-धीरे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव शरीर, खासकर हृदय पर देखने को मिलता है।

इम्यूनिटी बढ़ाने का असरदार उपाय है मेथी दाना का पानी

नई दिल्ली , एजेंसी। आयुर्वेद में बताए गए इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ प्राकृतिक उपाय लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। इन्हीं में से एक असरदार घरेलू उपाय है मेथी दाना का पानी, जिसे सुबह खाली पेट पीना स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, मेथी दाना में गैलेक्टोमैनन नामक खास प्रकार का फाइबर पाया जाता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित रूप से मेथी पानी पीने से शरीर में शुगर लेवल संतुलित रहता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता भी बेहतर होती है। यही कारण है कि डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए यह एक प्रभावी प्राकृतिक उपाय माना जाता है, जो शुगर स्पाइक्स को नियंत्रित करने में मदद करता है। वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी मेथी दाना का पानी काफी उपयोगी साबित होता है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और भूख को नियंत्रित करता है, जिससे अनावश्यक कैलोरी का सेवन कम हो जाता है।

इसके नियमित सेवन से धीरे-धीरे वजन घटने में मदद मिलती है और शरीर फिट रहने लगता है। पाचन तंत्र को मजबूत

बनाने में भी मेथी पानी अहम भूमिका निभाता है। जिन लोगों को गैस, अपच, एसिडिटी या कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए यह एक आसान और असरदार उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर पेट की सफाई करता है और पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पेट हल्का रहता है और दिनभर ऊर्जा बनी रहती है। दिल की सेहत के लिए भी मेथी दाना फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे हृदय रोगों का खतरा घटता है। साथ ही यह ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में भी सहायक होता है, जिससे हार्ट अटैक का जोखिम कम हो सकता है।

इसके अलावा, मेथी पानी जोड़ों के दर्द और गठिया जैसी समस्याओं में भी राहत पहुंचाता है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस साधारण घरेलू उपाय को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए, तो यह न केवल शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों से बचाव में भी मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि बढ़ते प्रदूषण, असंतुलित खानपान और खराब जीवनशैली के कारण आजकल लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से कमजोर हो रही है। इसका असर यह होता है कि लोग छोटी-छोटी बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं।

पौधों की देखरेख के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रणाली लागू

गोरखपुर , एजेंसी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शुक्रवार को स्वच्छता पखवाड़ा के तहत पौधरोपण अभियान का आयोजन किया गया। यह अभियान संस्थान परिसर में हरित आवरण बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से चलाया गया। अभियान में एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग के 40 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने पौधारोपण के साथ उन्हें अपनाने की पहल भी की। खास बात यह रही कि पौधों की देखरेख के लिए क्यूआरकोड आधारित प्रणाली लागू की गई।

7 चीजों को आहार में शामिल करने से महिलाएं रहेगी स्वस्थ

नई दिल्ली , एजेंसी। आधुनिक जीवनशैली और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं में पोषक तत्वों की कमी, हार्मोन असंतुलन और कमजोरी जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। ऐसे में संतुलित और पोषक आहार बेहद जरूरी हो जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ प्राकृतिक और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थों को रोजाना आहार में शामिल करके महिलाएं अपने शरीर की कई कमियों को दूर कर सकती हैं। इनमें सबसे पहले रागी का नाम आता है, जो कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होती है। रागी का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने, हार्मोन संतुलित रखने और त्वचा

व बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसे रोटी, चीला या लड्डू के रूप में आसानी से खाया जा सकता है। दूसरे स्थान पर आंवला है, जो विटामिन-सी का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और संक्रमण से बचाव में सहायक होता है। आंवले का सेवन जूस, चटनी, अचार या मुरब्बे के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा चिया सीड्स भी महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद हैं। इनमें कैल्शियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, कमजोरी दूर करता है और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इसी तरह अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, मानसिक तनाव कम करते हैं और हार्मोन से जुड़ी समस्याओं, जैसे पीसीओडी, में भी लाभकारी साबित होते हैं। कद्दू के बीज भी पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें मैग्नीशियम और जिंक जैसे जरूरी तत्व होते हैं, जो शरीर की कई प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। इनकी कमी से थायराइड जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए रोजाना थोड़ी मात्रा में इनका सेवन लाभदायक है। बढ़ती उम्र के साथ शरीर और मस्तिष्क की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए अखरोट का सेवन भी जरूरी माना जाता है। यह दिमाग को तेज रखने और जोड़ों से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करता है।

वहीं, चुकंदर महिलाओं में खून की कमी को दूर करने के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सात चीजों को नियमित आहार में शामिल करने से महिलाएं अपनी सेहत को बेहतर बना सकती हैं और कई बीमारियों से बचाव कर सकती हैं।

फरीदाबाद में वकील की सलाह पर 29 साल तक बेखबर रहा शख्स

शराब केस में लगा 5000 रुपये का जुर्माना

फरीदाबाद, एजेंसी। वकील के कहने पर मुकदमा खत्म समझकर आराम से घर बैठे खेड़ी कलां गांव निवासी 65 वर्षीय चंद्रभान उर्फ पप्पू के घर जब पुलिस गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंची तो उसे पता चला कि 29 साल पहले उस पर दर्ज हुआ अवैध रूप से शराब ले जाने का मुकदमा अभी चल रहा है। इधर पता चलने पर चंद्रभान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने याचिका रद करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती जो पहले से भगोड़ा घोषित है। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। न्यायाधीश नवीन कुमार की अदालत में आरोपित ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने चंद्रभान को दोषी करार देकर पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस तरह करीब तीन दशक पुराना मुकदमा खत्म हुआ।

शराब बंदी के समय का था मामला

साल 1997 के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी लागू की थी। 29 अगस्त 1997 को ओल्ड फरीदाबाद थाना में तैनात एएसआइ रामदत्त ने गश्त के दौरान चंद्रभान को एक थैले में देसी शराब के 90 पाउच ले जाते पकड़ा था। थाने में एक्साइज एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने इसके बाद आरोपित को जमानत पर छोड़ दिया गया। इधर एक अप्रैल 1998 को शराबबंदी का आदेश वापस ले लिया गया। इसके बाद आरोपित के वकील ने कहा कि अब मुकदमा खत्म हो गया है। अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। चंद्रभान ने भी विश्वास कर लिया जबकि अदालत की कार्रवाई में तो मुकदमा चलता रहा। अदालत की तरफ से नियमानुसार चंद्रभान को पेश होने के नोटिस जारी किए गए, मगर वह पेश नहीं हुआ और 27 सितंबर 2000 में भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इस साल की शुरुआत में पुलिस ने लंबे समय से भगोड़ा चल रहे आरोपितों के खिलाफ अभियान चलाया तो उसमें चंद्रभान का भी नाम था। पुलिस ढूंढते हुए उसके घर पहुंची, तो पता चला कि अभी मुकदमा जारी है। अब जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो सुनवाई के दौरान चंद्रभान ने अदालत को बताया कि वह अशिक्षित है, इसलिए वकील की बात पर भरोसा कर लिया, साथ ही यह भी कहा कि अदालत के कोई नोटिस नहीं मिले। इसलिए वह अदालत में पेश नहीं हुआ। अंततः अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा कर मामले का पटाक्षेप किया।